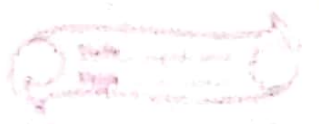


11/09/20



Food Problem in India :

खाद्य उत्पादन एवं जनसंख्या के बीच घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक का विचार था कि खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तेजी से होगी है। भारत वर्ष में वृद्धि आगामी तक खाद्यान्न उत्पादन और जनसंख्या के महत्व लगातार संतुलन की स्थिति थी, परन्तु 20वीं आगामी के आरम्भ से ही जनसंख्या खाद्यान्न की तुलना में अधिक बढ़ने लगी और खाद्य समस्या की स्थिति उत्पन्न हो गई।

भारत में खाद्य-समस्या के चार पहलू हैं : →

1. साम्राज्यिक पहलू : - इसका सम्बन्ध खाद्य-समस्या की तुलना में और तुलना से है। इस रूप में खाद्य-समस्या एक उत्पन्न-कालीन संकट नहीं, बल्कि एक दीर्घ-कालीन आघात की दशा मानी जाती है। खाद्य-समस्या का उत्पादन बढ़ाकर ही माँग और पूर्ति में आयत्तम संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

2. गुणात्मक पहलू : → अधिकांश देशवासियों को आवश्यक नित्य जीवन मिलता है। हमारे जीवन में दूध, फल, माँस

आदि रक्षात्मक पदाथों का आभाव रहता है, आतं लोगों की पर्याप्त मात्रा में भोजन तक नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य लाभ की कार्यक्षमता कम होती है और यह दुर्बल रहता है। आतं स्वास्थ-समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सर्वस्वास्थ्य को सन्तुलित और पारिष्टिक भोजन मिलना चाहिए।

उ. प्रशासनिक पहलू :- इसका संबंध स्वास्थानों के वितरण पक्ष से है, न कि उत्पादन पक्ष से। उचित एवं प्रभावपूर्ण सरकारी स्वास्थ-नीति ही स्वास्थ-समस्या के इस रूप का निराकरण कर सकती है।

द. आर्थिक पहलू :- भारत में अनेक बार यह भी देखने में आता है कि महंगे अनाज की खरीदने के लिए लोगों के पास आवश्यक क्रय-शक्ति का आभाव रहता है। आतं 'अनाज के आभाव' के स्थान पर 'मुद्रा का आभाव' पाया जाता है। इस पहलू का सम्बन्ध सामान्य जनता की गरीबी तथा स्वास्थानों के उच्च भाव से होता है।

भारत में स्वास्थान आभाव के कारण
भारत में स्वास्थान आभाव के लिए

निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं :-

1. जनसंख्या में वृद्धि ।
2. कृषि के पुराने तरीके ।
3. प्राकृतिक प्रकोप ।
4. एमापारिक कृषि का विस्तार ।
5. घटती कृषि भूमि ।
6. दोषपूर्ण सरकारी नीति ।
7. उत्पादकता का निम्न स्तर ।
8. निर्व्यनता और वैरोजगारी ।
9. एमापारियों की दूषित भव्यता ।

भारत में खाद्य समस्याएँ हल करने के निम्नलिखित प्रयास भारत सरकार द्वारा किए गए हैं :-

1. खाद्य विभाग की स्थापना ।
2. अतिरिक्त उन्नत उपजाऊँ अनादीकरण ।
3. कृषि व ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता ।
4. अनाज का आयात ।
5. सुरक्षित भण्डार ।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
7. भारतीय खाद्य निगम की स्थापना ।
8. केंद्रीय भण्डारण निगम ।
9. अतिरिक्त उपज देने वाले किस्मों को अपनाया जाना ।
10. भूमि तथा जल संरक्षण कार्यक्रम ।
11. उन्नत कृषकों को आश्रय ।
12. सुर्वरकों का प्रयोग ।
13. उन्नत बीजों का उत्पादन एवं वितरण ।

- 14. एच.पि. - उद्योग निगम की स्थापना ।
- 15. राष्ट्रीय एच.पि. उद्योग की स्थापना ।

समाप्तः